उत्पादन के लिये राजस्थान में खेतड़ी में एक एकीकृत कम्पलैक्स की स्थापना कर रही है। हिन्दुस्तान कापर कारपोरेशन बिहार में राखा खान-रोम सिद्धेश्वर खंड और आन्ध्र प्रदेश में अग्निगुन्डाला क्षेत्र के तांबे के उपयोग के लिये भी कदम उठा रही है।

All India Railway Commercial Clerks' Association

*784. SHRI SHRI CHAND GOYAL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have received some representations from the All-India Railway Commercial Clerks' Association regarding the increase in per-centage of their departmental promotions; and

(b) if so, the action taken by Government in this behalf ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) Yes; Sir.

(b) The matters raised are under examination.

दिल्ली शाहदरा से सहारनपुर तक बड़ी रेलवे लाइन

*791. **श्री हरदयाल देवगुण:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि शाहदरा सहारनपुर लाइट रेलवे में यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है और इस रेलवे पर यात्रा में बहुत अधिक समय लगता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस रेल मार्ग पर बड़ी लाइन बिछाने और तेज गति वाली रेल चलाने का है;

(ग) यदि हां, तो इस निर्णय को कब तक कार्यरूप दिया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस रेलवे पर यात्रा करने वाले यात्रियों को आराम और सुविधा देने के संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) प्राइवेट कम्पनी द्वारा परिचालित इस लाइन के बारे में इस प्रकार की कुछ शिकायतें मिली हैं।

(ख) और (ग). इस लाइट रेलवे को बड़ी लाइन में बदलने की सम्भावना का पता लगाने के लिए टोह इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण की हाल में मंजूरी दी गई है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने और रेलवे बोर्ड द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच कर लेने के बाद बड़ी लाइन के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा।

(घ) ऊपर भाग (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

Crisis in Aluminium Industry

*792. SHRI S. S. KOTHARI:
SHRI GADILINGANA GOWD:

Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the aluminium industry is faced with accumulation of stocks due to slackening of demand for its products;

(b) if so, the reasons for which substantial quantities of aluminium were imported; and

(c) the steps Government and the industry are taking to resolve the crisis ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI P. C. SETHI): (a) During June-July 1968 representations were received from the aluminium producers regarding accumulation of stocks with them due to fall in domestic demand and the recession in the cable and conductor industry.

(b) During the earlier years, the indigenous production of E.C. grade aluminium was not sufficient to meet the demand of the ACSR/AAC industry and thus imports of E. C.

grade were allowed to the actual users under the liberalised import policy.

(c) On receipt of the representations from the indigenous producers the position was immediately reviewed and the import of the metal has since been put under 'Actual User Restricted' category. Exports of aluminium from India are also being allowed. The position regarding actual production of aluminium in the country, stocks with the producers etc. is being watched carefully and at present the industry does not carry heavy stocks of the metal.

ट्रैक्टरों का निर्माण

*793. **श्री महाराज सिंह भारती :**
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रैक्टर बनाने के काम के लिए लाइसेंस लेने की शर्त हटाई जाने के बाद अब तक कितने ट्रैक्टर निर्माताओं से आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे; कितने आवेदन पत्रों पर अन्तिम निर्णय कर लिए गये हैं और कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं;

(ख) क्या यह सच है कि निर्णय करने में सरकार कई वर्ष लगा देती है और इससे ट्रैक्टरों के निर्माण में बाधा पड़ती है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि ट्रैक्टरों की वार्षिक मांग बढ़कर एक लाख हो गई है परन्तु उनके निर्माण का लक्ष्य केवल 20 हजार है यदि हां, तो बढ़ी हुई मांग कैसे पूरी की जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद) : (क) ट्रैक्टर उद्योग को लाइसेंस प्राप्त करने के उपबन्धों से मुक्त किए जाने के समय से आजतक विदेशी सहयोग से ट्रैक्टर बनाने वाले उपक्रम स्थापित करने के छः आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से एक आवेदन को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है और संबंधित फर्म को कहा गया है कि वह अन्तिम रूप से सहयोग करार, पुनरीक्षित प्रावस्था-आजित निर्माण कार्यक्रम तथा पंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए आवेदन प्रस्तुत करे। दो अन्य फर्मों को भी जिनके प्रकरण में विदेशी सहयोगियों को एक मुश्त राशि तथा आवर्ती स्वामिस्व देय नहीं है को भी पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए आवेदन देने तथा पुनरीक्षित प्रावस्था अर्जित कार्यक्रम को सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। वे अभी प्रतीक्षित हैं। एक आवेदक को कहा गया है कि वह अपने प्रस्तावित ट्रैक्टर जिसे वह बनाना चाहता है की परीक्षा मध्य-प्रदेश में बुदनी स्थित ट्रैक्टर परीक्षणशाला में आवेदन पर अंतिम निर्णय लेने से पूर्व कराये। शेष हाल ही में प्राप्त दो योजनाओं की जांच की जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) कृषि विभाग ने 1973-74 में ट्रैक्टरों की मांग को 90,000 नग प्रतिवर्ष आंका है। जबकि ट्रैक्टरों का देशीय उत्पादन 50,000 नग होगा। इस क्षेत्र में विद्यमान एककों द्वारा और अतिरिक्त क्षमता स्थापित करके ट्रैक्टरों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सभी पग उठाए जा रहे हैं। इस समय देशीय ट्रैक्टरों की उपलब्धि तथा ट्रैक्टरों की मांग के अन्तर को रुपये में अदायगी किए जाने वाले देशों से निर्मित ट्रैक्टरों के आयात से पूरा किया जा रहा है।

Production of Iron ore in Bellary Hospet Mines

*794. SHRI BHOGENDRA JHA: Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4497 on the 20th August, 1968 and state:

(a) whether information has been collected with regard to the abundance of power and water near the Bellary Hospet mines;

(b) whether any comparative economic advantage of exporting the best quality iron ore from those mines and of exporting steel made out of the quantity being exported, has been or is being worked out;